Title: Need to increase Minimum Support Price for foodgrains.

श्री जे.एस. बरार (फरीदकोट) : अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस देश की आबादी का 70 प्रतिशत हिस्सा जो किसान हैं, उनकी समस्या को उठाने का मौका दिया। भारत सरकार ने पहली अप्रेल से गेहूं की खरीद का ऐलान किया है। जो ऐलान की गई कीमत है, वह 620 रुपए प्रति क्विंटल है, जो पिछले वर्ष की थी, उसका ऐलान किया गया है। मैं पहली बात यह कहना चाहता हूं कि 1970-71 को बेस ईयर मानकर एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के पास जो यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट आई है, वह कम से कम 885 रुपए प्रति क्विंटल है, जिससे किसानों की पूर्ति होती है, अगर यह मिनीमम सपोर्ट प्राइस उसे मिल जाए। मुझे लगता है कि सरकार ने किसान विरोधी केलकर समिति की रिपोर्ट को पहले से ही लागू करना शुरू कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा तय यह कीमत बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि पंजाब के पास जो सबसे ज्यादा सेंट्रल पूल में योगदान है, 11500 करोड़ रुपए का स्टाक है, यानी 175 लाख टन अनाज हमारे गोदामों में पड़ा सड़ रहा है।

हमारी शिकायत यह है कि किसानों को न तो रेलवे से उचित रेट मिल रहा है न एफसीआई से ठीक रेट मिल रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया सुमा जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पंजाब का 5 हजार करोड़ रुपया एफसीआई के ऊपर पेंडिंग है। किसानों को न उचित रेट मिल रहा है न रिलीजिंग आर्डर मिल रहा है। पंजाब डूब रहा है और किसानों की फसल का स्टॉक क्लीयर नहीं होता। लगभग 95 प्रतिशत स्टॉक गोदामों के बाहर पड़ा हुआ है। भारत सरकार को इस ओर तुरंत कदम उठाने चाहिए।